The Commission feels that an appropriate Committee may be set up for expeditious payment of reasonable compensation in such cases.

It has been agreed by the Government that instead of reasonable compensation, reasonable ex-gratia amount should be given. The modalities will be got worked out within a period of three months in consultation with the concerned State/UT Governments.

Military action in Jafna by Sri Lankan Government

46. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA:

SHRI SURAJ PRASAD:

Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Sri Lankan Government have embarked upon a total military action in Jaffna with major airborne assaults, killing a large number of Tamil civilians; and

(b) if so, what is the reaction of the Government of India with regard thereto stating the setback in the talks with Sri Lankan Government to solve the ethnic problem as a consequence of military action?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI K. NATWAR SINGH): (a) Yes, Sir. Starting from early January there has been an escalation by the Sri Lankan Government of its military offensive in the Jaffna area which included aerial bombing. Reports indicate a large number of civilian deaths.

(b) Government have conveyed their serious concern at the escalating military action by the Sri Lankan Government and have let it be known that this could affect Government's policy on the Sri Lankan situation.

हिन्दी सलाहकार समिति की बैठकें

47. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले 18 वर्षों से वार्षिक प्रगामी हिन्दी कार्यक्रम के चलते रहने के बाद भी, इन वर्षों के दौरान एक वर्ष के कार्यक्रम को भी पूरा न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि प्रधानमंत्री ने 19 सितम्बर, 1985 को विज्ञान भवन में यह आग्रह किया था कि 1985-86 के वर्ष के लिए वार्षिक कार्यक्रम अवश्य पूरा किया जाये, लेकिन बार-बार आग्रह के बाद भी उनके मंत्रालय द्वारा भी इसे पूरा नहीं किया गया ;

(ग) मंत्रालय में हिन्दी सलाहकार समिति के गठन के बाद से उसकी कितनी बैठकें हुई हैं और प्रत्येक वर्ष हुई ऐसी बैठकों की औसत संख्या कितनी रही है ; और

(घ) क्या यह सच है कि उनके मंत्रालय तथा राजभाषा विभाग ने हिन्दी के कार्यान्वयन संबंधी कार्य को कभी भी गंभीरता से नहीं लिया है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों, कार्यालयों, उपक्रमों आदि द्वारा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए एक वार्षिक कार्यक्रम इस उद्देश्य से जारी किया जाता है कि मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों द्वारा उसमें निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए । विभिन्न मंत्रालयों, विभागों से प्राप्त प्रगति रिपोर्टों के आधार पर यह देखने में आया है कि केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में पिछले वर्षों में हिन्दी के प्रगामी प्रयोग में निरन्तर प्रगति हुई है ।

(ख) जी नहीं, श्रीमन्, प्रधानमंत्री द्वारा 19 सितम्बर, 1985 को विज्ञान भवन में इस प्रकार का विशेष आग्रह नहीं किया गया ।

(ग) वर्ष 1964 में हिन्दी सलाहकार समिति के गठन के बाद से 28 बैठकें आयोजित की गई हैं । वर्षवार आयोजित बैठकों की स्थिति इस प्रकार है :

1967—2
1968—2
1969—3
1970—3
1972—1
1973—2
1974—3
1975—2
1978—1
1979—2
1981—1
1982—2
1985—1
1986—3

(घ) जी नहीं, श्रीमन्, गृह मंत्रालय और राजभाषा विभाग द्वारा इस संबंध में निष्ठापूर्वक प्रयास किये जा रहे हैं ।

हिन्दी का वार्षिक प्रगामी कार्यक्रम

48. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि 1986-87 के वर्ष के लिए राजभाषा विभाग का वार्षिक प्रगामी हिन्दी कार्यक्रम, जो 31 मार्च, 1986 तक भेजा जाना था, सभी संस्थानों और मंत्रालयों को समय पर नहीं भेजा गया ;

(ख) क्या यह भी सच है कि केन्द्रीय सरकार के 61 मंत्रालयों/विभागों में केवल 36 हिन्दी सलाहकार समितियां बनायी गई हैं और उनकी दो से भी कम बैठकें हुई हैं जबकि मंत्रालयों में एक वर्ष में कम से कम चार बैठकें कराया जाना आवश्यक है ; और

(ग) क्या यह सच है कि स्वयं मंत्रालय, जिसके प्रभाराधीन राजभाषा विभाग कार्य कर रहा है, राजभाषा अधिनियम का पालन नहीं करता है, और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

गृह मंत्रालय में राज मंत्री (श्री चिन्तामणि पाणिग्रही) : (क) संघ की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन के लिए बनाया गया वार्षिक कार्यक्रम 1986-87, 1 अप्रैल, 86 से लागू है । छपाई की कुछ व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण इसे उस तारीख तक छपवाया नहीं जा सका । छपी हुई प्रतियां हमें जून, 1986 के दूसरे सप्ताह में मिलीं और उसके बाद तुरन्त सभी मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों को इन्हें वितरित करने का काम हाथ में ले लिया गया ।

(ख) केन्द्रीय सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों के लिए चौंतीस (34) हिन्दी सलाहकार समितियों का गठन किया गया है । इनके गठन/पुनर्गठन की तिथियां और 1986 से अब तक हुई इनकी बैठकों की संख्या संलग्न विवरण में दी गई हैं **(नीचे देखिये)** । निर्देशों के अनुसार इनकी बैठकें तीन महीने में एक बार होनी चाहिए ।

(ग) जी नहीं ।